67 बनाम 3 : आजादी के 70 वर्ष

1947 में आजादी के अवसर पर महात्मा गांधी जी से पूछा गया था कि अब आपकी आजाद भारत की परिकल्पना क्या है? उन्होंने जवाब दिया, 'शासक और शासन विहीन समाज की'। अर्थात समाज खुद इतना अनुशासित हो कि किसी को उस पर शासन करने की आवश्यकता न पड़े।

पंडित नेहरू ने भारत की आजादी का बिगुल फूंकते हुए उद्घोष किया, 'अब हम आजाद हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, धर्म के आचरण के लिए, सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए, भाषा के लिए और संस्कारों के सरोकारों को लेकर' और वायदा किया कि अब न्याय के सम्मुख सब समान होंगे।

रणदीप सिंह सुरजेवाला

इन्हीं बुनियादी विचारों को आधार बनाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के नेतृत्व में देशभर के कानूनविद, कलाकार, साहित्यकार, कलमकार, इतिहासकार, खेतीहर, लगभग हर क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोग संविधान सभा के माध्यम से एकत्रित हुए और हमने एक जनवादी संविधान का निर्माण किया तथा आजाद भारत के प्रगति के पथ पर संविधान को आधार बनाकर प्रजातंत्र के रास्ते पर चलना आरम्भ किया।

प्रजातंत्र के इस प्रशस्त मार्ग को हमारे कई बड़े नेताओं ने मील के पत्थरों से सुशोभित करना प्रारम्भ किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी और एक अग्रिम आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में निर्णायक भूमिका भी निभाई। लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान- जय किसान' के नारे के साथ, इंदिरा ने 'हरित क्रांति' व 'गरीबी हटाओ' को एक नया आकार देकर, राजीव गांधी ने '21वीं सदी के भारत' की संरचना के साथ-साथ 'कम्प्यूटर व सूचना क्रांति' का पदार्पण किया तथा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक अधिकारों का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। जहां नरसिम्हा राव ने आर्थिक क्रांति की शुरूआत की वहीं सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राजनीतिक नेतृत्व को इस बात का साफ आभास था कि अब देश की प्रगति के आगे का रास्ता आर्थिक तरक्की के साथ समावेशी विकास का है।

तो जहां एक ओर परमाणु संधि से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति की नई इबारतें लिखी गईं तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों को उनके अधिकारों को सौंपने का क्रम प्रारम्भ कर दिया गया। आदिवासियों को उनकी वनभूमि का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, देश की 67 प्रतिशत आबादी को भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, किसानों को उनकी भूमि के उचित मुआवजे का अधिकार, मनरेगा के तहत काम का अधिकार, गांवों को बिजली का अधिकार तथा गरीबों को स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। एक तरह से देश के नागरिकों को उनके प्रजातंत्रीय अधिकार कानूनी रूप से उन्हें सौंप दिए गए।

लगातार 10 वर्षों तक रोज सुबह समाचारों की सुर्खियों को याद कीजिए। बहस के मुद्दे क्या थे, पक्ष और प्रतिपक्ष के? कभी अमरीका से परमाणु संधि, कभी आदिवासियों के वन अधिकार का कानून, कभी 86 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा का कानून, कभी किसानों के भूमि के अधिकार का कानून। अर्थात अगर समग्रता से देखें तो 2014 तक बीते 67 वर्षों में हमने अपने प्रजातंत्र के लंबे सफर में अपनी मंजिल तक पहुंचने में किसी हद तक बहुत कामयाबी हासिल की है।

मगर बीते 3 वर्षों में हमने महसूस किया कि प्रजातंत्र के मील के पत्थरों पर कुछ नई परिभाषा लिखने की कोशिश की गई है, जिससे देश की प्रगति का पथ न सिर्फ अवरुद्ध हुआ है अपितु उससे मंजिल भी दिखाई नहीं देती।

प्रजातंत्र की स्थापित सामूहिक मान्यताओं को मनमानियों में तबदील कर दिया गया है। देश के बहुलतावादी विचारों का सामूहिक गान आज बेसुरे एकल गीत के रूप में परोसा जा रहा है। विचार कीजिए कि देश की जो बहस थी, जो समाचारों की सुर्खियां थीं, अधिकारों की, किसानों के खेतों की, आदिवासियों के घरों की, छात्रों की शिक्षा की, नागरिकों की सूचना की, गरीबों के राशन की, वे किसमें तबदील कर दी गई हैं। वे सुर्खियां आज भीड़ द्वारा हमलों व हत्याओं में, आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं में, कभी श्मशान-कब्रिस्तान की बेवजह चर्चाओं में, कभी दीवाली-रमजान के बंटवारे में, कभी घर वापसी में, कभी एन्टी रोमियो स्क्वायड में, कभी बूचड़खानों में तबदील कर दी गई हैं।

और ये सब इसलिए कि वर्तमान सरकार नागरिकों से किए अपने वायदों को निभाने में नाकामयाब रही है, इसलिए वह चाहती है कि समाचार की सुर्खियों के स्वर बदल कर नाकामियों पर पर्दा डाल दिया जाए। प्रजातंत्र की मूल भावनाओं को आहत कर प्रतिपक्षी सरकारों को अनैतिक तरीके से तोड़ा जा रहा है। कहीं संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से प्रतिपक्षीय सरकारों को न बनने देकर स्वयं की अल्पमत की सरकारों को बनाया जा रहा है। अंतत: जो 67 वर्षों का एक प्रशस्त मार्ग देश के प्रजातंत्र ने तय किया था, उसको बीते 3 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संक्रमण काल की पथरीली राहों पर धकेला जा रहा है।

मगर फिर भी हमें अपने देश के नागरिकों पर आस्था है और यह ताकत प्रजातंत्र में उन्हीं के हाथ में है कि वे महात्मा गांधी के अनुशासित प्रजातंत्र के स्वप्न को साकार करें और सरकार को सही रास्ते पर लाएं ताकि फिर हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले।

rssurjewala@gmail.com